भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं.4914**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमेरिका की व्यापार नीति

4914. श्री ससिकांत सेंथिल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर हाल ही में लगाए गए अमरीकी प्रशुल्क के भारत के साथ इन देशों के व्यापार संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या हैं।

(ख) सरकार की इन देशों से संभावित प्रतिकारी प्रशुल्क, जो भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं, से निपटने की क्या योजना है;

(ग) सरकार द्वारा अमरीकी व्यापार नीतियों के कारण बढ़े हुए प्रशुल्क और इन चुनौतियों के कारण उत्पन्न होने वाले आर्थिक व्यवधानों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार उद्योगों को वैश्विक व्यापार तनाव से बचाने के लिए अन्य व्यापार नीतियों अथवा समझौतों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): दिनांक 1 फरवरी, 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशेष रूप से बिजली, प्राकृतिक गैस और तेल सहित कनाडाई ऊर्जा निर्यात के लिए 10% टैरिफ के साथ मेक्सिको और कनाडा से आयातित सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने हेतु कार्यकारी आदेश जारी किए। प्रशुल्कों को दिनांक 4 मार्च, 2025 को लागू किया गया था। दिनांक 4 मार्च, 2025 को चीनी वस्तुओं पर प्रशुल्क दर 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई । भारत सरकार इन प्रशुल्क घोषणाओं के प्रभाव और भारतीय व्यापार पर मेक्सिको, चीन और कनाडा द्वारा संभावित जवाबी प्रशुल्कों की बारीकी से निगरानी कर रही है। मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर टैरिफ के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले नए

अवसरों की पहचान करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। समानान्तर रूप से, डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत उचित सुरक्षा उपायों के लिए आयात की निगरानी की जा रही है, यदि मेक्सिको, चीन और कनाडा सहित बढ़ते आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान होता है या खतरा होता है।

(ग) और (घ): भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी और निष्पक्ष तरीके से द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ निरंतर कार्य कर रही है। दोनों देशों ने 13 फरवरी, 2025 को एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। दोनों देशों वर्ष 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्र द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत दोनों देश बाजार तक पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाने और प्रमुख व्यापार संबंधी मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

*****